[2015]1 एस. सी. आर 849

भारत संघ और अन्य

बनाम

पुरुषोत्तम

(सिविल अपील संख्या 7133/2008)

05 जनवरी, 2015

[न्यायाधिपति विक्रमजीत सेन औरन्यायाधिपति शिवा कीर्ति सिंह]

सेवा कानून-विभागीय जांच-अनुमति - सारांश कोर्ट मार्शल (एससीएम) कार्यवाही यू/आर 133 सेना नियमों की - आरोपित अपराधों के लिए अपराधी को दोषी ठहराना - धारा के तहत कार्य करने वाला समीक्षा प्राधिकारी। सेना अधिनियम की धारा 162 ने एससीएम कार्यवाही को आरोपों के गलत निर्धारण और सबूतों की अपर्याप्त रिकॉर्डिंग के आधार पर रद्द कर दिया - इसके बाद सेना के अधिकारियों ने अपराधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हीं आरोपों का आरोप लगाया गया जिसके लिए एससीएम कार्यवाही शुरू की गई थी और बाद में अलग कर दी गई - समाप्ति अपराधी की सेवाएँ - समाप्ति को चुनौती देने वाली रिट याचिका - उच्च न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस को रद्द करते हुए याचिका को अनुमति दी - हालाँकि, अदालत ने अपराधी को विभागीय कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोका - अपील पर, माना: एक आपराधिक अदालत द्वारा किसी कर्मचारी को बरी करना नहीं होगा स्वचालित रूप से और निर्णायक रूप से विभागीय कार्यवाही पर प्रभाव डालता है - जब तक अपराधी सम्मानजनक बरी नहीं हो जाता, विभागीय कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता है - वर्तमान मामले में अपराधी ने सम्मानजनक बरी नहीं अर्जित किया है, विभागीय

कार्यवाही से नहीं रोका जा सकता है - सेना अधिनियम, 1950 - धारा 162 सेना नियम - आर 133।

सेना नियम, 1950 - आर. 133 - सारांश कोर्ट मार्शल कार्यवाही यू/आर. 133 - की समीक्षा - आयोजित: आर. 133 उप-न्यायाधीश-महाधिवक्ता को समीक्षा प्राधिकारी के रूप में सशक्त नहीं करता है, बल्कि केवल अग्रेषण कार्य प्रदान करता है - सारांश कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष और सजा को समीक्षा प्राधिकारी द्वारा अबाधित छोड़ दिया जाना चाहिए- सेना अधिनियम, 1950 –धारा 161(1)

सेना अधिनियम, 1950 – धारा 121 - प्रयोज्यता - का दायरा - आयोजित: धारा 121 ऑट्रेफॉइस दोषमुक्ति और ऑट्रेफॉइस दोषी को कला से भिन्न मानता है। संविधान का 20(2) जो केवल ऑट्रेफोइस को दोषी ठहराता है - हालाँकि, धारा 121 के तहत इन्सुलेशन केवल दूसरे कोर्ट मार्शल या यू/एसएस के तहत व्यवहार तक ही सीमित है। अधिनियम के 80, 83, 84 और 85 - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 20(2)।

भारत का संविधान, 1950 - कला 20(2) - दोहरे ख़तरे का सिद्धांत - की प्रयोज्यता - सारांश कोर्ट मार्शल कार्यवाही को रद्द कर दिया गया - बाद में आरोपों के एक ही सेट पर अपराधी को कारण बताओ नोटिस - माना गया: कला 20(2) नहीं करता है इसके अंतर्गत, ऑट्रेफॉइस बरी के सिद्धांत को आत्मसात करें - इसलिए, बाद की "विभागीय या अनुशासनात्मक कार्यवाही, भले ही आयाम में दंडात्मक हो, नहीं होगी अनुच्छेद 20(2) द्वारा गैरकानूनी - वर्तमान मामले में अपराधी को विभागीय कार्यवाही से बाहर नहीं किया गया है।

क़ानून की व्याख्या - नियमों की व्याख्या - माना गया: नियमों की व्याख्या ऐसे तरीके से की जानी चाहिए जो उन्हें मूल क़ानून के अनुरूप बनाए रखे - यदि नियम किसी ऐसे कार्य को निर्धारित करते हैं जिस पर क़ानून द्वारा विचार नहीं किया गया है,

तो यह अत्यधिक प्रत्यायोजन के दोष से ग्रस्त होगा और इस प्रकार यह अधिकारातीत होगा।

कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1. संविधान के निर्माता ऑट्रेफॉइस बरी और ऑट्रेफॉइस दोषी की भिन्न और असमान अवधारणाओं के प्रति पूरी तरह से सचेत थे और जानबूझकर उन्होंने दोहरे खतरे के सिद्धांत को केवल अभियोजन पक्ष तक सीमित रखने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई। संविधान का अनुच्छेद 20(2) ऑट्रेफॉइस बरी के सिद्धांत को आत्मसात नहीं करता है। फोर्टियोरी अनुच्छेद 20(2), जो "मुकदमा चलाने और दंडित करने" पर विचार करता है और इस प्रकार ऑट्रेफॉइस बरी के सचेत बहिष्कार को दर्शाता है, स्पष्ट रूप से यह मानता है कि निर्धारित क्रमिक सजा एक आपराधिक चरित्र की होनी चाहिए। यह निर्विवाद रूप से इस बात का अनुसरण करता है कि विभागीय या अनुशासनात्मक कार्यवाही, भले ही आयाम में दंडात्मक हो, अनुच्छेद 20(2) द्वारा गैरकानूनी नहीं होगी। [पैरा10 और 12] (862-एच; 863-ए; 865-एफ-एच)

मकबूल हुसैन बनाम बॉम्बे राज्य 1953 एससीआर 730 - अनुसरण किया गया।

आर. पी. कपूर बनाम भारत संघ एआईआर 1964 एससी 787: 1964 एससीआर 431 - अनुचित ठहराया गया।

आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले (1984) 2 एससीसी 183:1984 (2)एससीआर 495; हल्दीराम भुजियावाला बनाम आनंद कुमार दीपककुमार (2000) 3 एससीसी 250: 2000 (1) एससीआर 1247; समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1997) 8 एससीसी 191: 1997 (2) पूरक एससीआर 305; बिहार राज्य बनाम मुराद अली खान (1988) 4 एससीसी 655: 1988 (3) पूरक एससीआर 455 – को संदर्भित

जॉन हडसन बनाम युनाइटेड स्टेट्स 522 यू.एस.93(1997); युनाइटेड स्टेट्स बनाम हेल्पर 490 यू.एस 436 (1989); युनाइटेड स्टेट्स बनाम वार्ड 448 यू.एस. 242 (1980) - संदर्भित।

2. आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी कर्मचारी को बरी करने से विभागीय कार्यवाही पर स्वचालित और निर्णायक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे पहले, यह दोनों में सबूत की असमान डिग्री के कारण है, अर्थात् आपराधिक अभियोजन में उचित संदेह से परे सिविल या विभागीय पूछताछ में प्रबल सबूत के विपरीत। दूसरे, आपराधिक अभियोजन संबंधित विभाग के नियंत्रण में नहीं है और दोषमुक्ति घटिया जांच या सबूतों को लापरवाही से आत्मसात करने या मुकदमे के लापरवाहीपूर्ण संचालन आदि का परिणाम हो सकता है। तीसरा, आपराधिक अभियोजन में बरी होने से विपरीत निष्कर्ष पर रोक लग सकती है। किसी विभागीय जांच में यदि पूर्व निर्णय निष्क्रिय निर्णय के विपरीत सकारात्मक निर्णय है जो तकनीकी कमजोरियों पर आधारित हो सकता है। दूसरे शब्दों में, आपराधिक न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि अभियुक्त निर्दोष है और न केवल यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वह उचित संदेह से परे दोषी साबित नहीं हुआ है। [पैरा 13] [866-डी-जी]

पुलिस उप महानिदेशक बनाम एस. समुथिराम (2013) 1एससीसी 598: 2012 (11) एससीआर 174 - पर भरोसा किया गया।

3. वर्तमान मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी ने सम्मानपूर्वक बरी कर दिया है। परिणामस्वरूप, चाहे दोहरे खतरे के सिद्धांत पर भरोसा करना हो या उसकी सजा को रद्द करना हो, विभागीय या अनुशासनात्मक कार्यवाही को वर्जित नहीं माना जाना चाहिए। [पैरा 14] [8&7-एफ-जी]

4. सेना अधिनियम की धारा 121 संविधान के अनुच्छेद 20(2) से अलग है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से ऑट्रेफॉइस को बरी करने और ऑट्रेफॉइस दोनों को कोर्ट-मार्शल

या आपराधिक अदालतों द्वारा मुकदमे के लिए दोषी ठहराती है, लेकिन फिर इन्सुलेशन को केवल एक सेकंड तक सीमित कर देती है। कोर्ट-मार्शल या सेना अधिनियम की धारा 80, 83,84 और 85 के तहत व्यवहार। [पैरा 16] [868-डी]

5. किसी विशेष कार्य को करने की शक्ति क़ानून में स्थित होनी चाहिए, और यदि क़ानून के तहत बनाए गए नियम किसी ऐसी कार्रवाई का आदेश देते हैं जिस पर क़ानून द्वारा विचार नहीं किया गया है, तो यह अत्यधिक प्रतिनिधिमंडल के दोष से ग्रस्त होगा और इस मंच पर अधिकारातीत माना जाएगा इसलिए, नियमों की व्याख्या ऐसे तरीके से की जानी चाहिए जो उन्हें मूल क़ानून के अनुरूप बनाए रखे। उच्च न्यायालय के समक्ष लगाया गया कारण बताओ नोटिस स्पष्ट रूप से प्रासंगिक तालिका के अवशिष्ट खंड 13(3)(111)(V) का सहारा लेते हुए, सेना नियमों के नियम 13 पर आधारित था। अपीलकर्ता सेना अधिनियम की धारा 20 का सहारा ले सकते थे। सेना अधिकारी अक्सर सेना अधिनियम के दायरे को पूरी तरह से समझे बिना ही सेना के नियमों में उलझे रहते हैं.. [पैरा19] [870-ई-जी]

6. सेना नियमों का नियम 133 उप-न्यायाधीश-महाधिवक्ता को समीक्षा प्राधिकारी के रूप में सशक्त नहीं करता है, बल्कि इसे केवल अग्रेषित करने का कार्य प्रदान करता है, नियम में कहा गया है कि सारांश कोर्ट मार्शल (एससीएम) की कार्यवाही को सक्षम करने के लिए अग्रेषित करना आवश्यक है। सेना अधिनियम की धारा 162 के तहत अधिकारी, लेकिन केवल मूल रूप से यह प्रावधान है कि यह "उप न्यायाधीश-महाधिवक्ता के माध्यम से" होगा। इसकी व्याख्या उपन्यायाधीश-महाधिवक्ता में धारा 162 के तहत समीक्षा करने वाले प्राधिकारी के वैधानिक अधिकार को स्थापित करने के रूप में नहीं की जा सकती है। [पैरा 23] [872-जीएच; 873-ए]

7. एक सारांश कोर्ट मार्शल को इसकी प्रभावकारिता, अंतिमता और वैधता के लिए, पुष्टि करने वाले प्राधिकारी की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि धारा

153 धारा 161 (1) में उल्लिखित कोर्ट मार्शल के अन्य तीन वर्गों के लिए अनिवार्य है, जो स्पष्ट रूप से बताता है कि निष्कर्ष और समरी कोर्ट मार्शल की सजा की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इसे तुरंत लागू किया जा सकता है। वर्तमान, धारा 162 के तहत कार्यवाही का प्रसारण होने के नाते, समीक्षा प्राधिकारी के इस आग्रह का आधार कि "दोषी नहीं" की याचिका दर्ज की जानी चाहिए और बाद में ऑफिसर कमांडिंग की अध्यक्षता में कोर्ट मार्शल के परिणामों को अलग करना, टिक नहीं सकता है . [पैरा 24] (873-सी-एफ)

8. प्रतिवादी ने समरी कोर्ट मार्शल सुनवाई में बचाव का कोई बयान नहीं दिया, और न ही अपनी ओर से कोई बचाव गवाह पेश किया और न ही अभियोजन पक्ष के दो गवाहों में से किसी से जिरह की। इन अपरिहार्य तथ्यों को देखते हुए, समीक्षा करने वाला प्राधिकारी ऐसे तकनीकी आधार पर कार्यवाही को रद्द नहीं कर सकता था। कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष और सजा को समीक्षा प्राधिकारी द्वारा अबाधित छोड़ दिया जाना चाहिए था, यह आत्मनिर्भर रूप से वैध था क्योंकि यह धारा 161 (1) के तहत था। सारांश कोर्ट मार्शल आदेश बहाल किया गया है। [पैरा 24 और 26](874-ए-सी, एफ) चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाम मेजर धर्मपाल कुकरेती 1985(2) एससीसी 412: 1985 (3) एससीआर 415 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम हरजीत सिंह संधू 2001 (5) एससीसी 593:2001 (2) एससीआर 1127 -पर भरोसा किया गया।

वाद कानून संदर्भ:

1984 (2) एससीआर 495	संदर्भित	पैरा 10
2000 (1) एससीआर 1247	संदर्भित	पैरा 10
1997 (2) सप्ल. एससीआर 305	संदर्भित	पैरा 10
1953 एससीआर 730	पालन किया	पैरा 10

1988(3)पूरक एससीआर 455	संदर्भित	पैरा 11
1964 एससीआर 431	अयोग्य आयोजित किया	पैरा 13
2012(11)एससीआर 174	संदर्भित	पैरा 13
1985 (3) एससीआर 415	पर निर्भर	पैरा 18
2001 (2) एससीआर 1127	पर निर्भर	पैरा 20

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7133/2008

2003 के सीडब्ल्यूपी 4254 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 21.4.2008 से।

के. राधाकृष्णन, आर.के. राठौड़, आर. बाला, एन.के. झा, बी.वी. बैरम दास, बी.कृष्ण प्रसाद अपीलकर्ताओं के लिए

प्रतिवादी की ओर से अरुण भारद्वाज, शेखर कुमार, डॉ. कैलाश चंद। .

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

न्यायाधिपति विक्रमजीत सेन

1. यहां प्रतिवादी संख्या 7773409 एक्स हवलदार (सैन्य पुलिस) पुरूषोत्तम को 7 जून 1983 को सैन्य पुलिस कोर में नामांकित किया गया था। 27 नवंबर 2001 को, जबकि प्रतिवादी को 916 प्रोवोस्ट यूनिट (जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, या जीआरईएफ) में तैनात किया गया था। उन्हें मोबाइल स्क्वाड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें उधमपुर-श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित विभिन्न ग्रीफ टुकड़ियों की जांच करने का काम सौंपा गया था। ड्यूटी पूरी होने पर, स्क्वाड कमांडर ने प्रतिवादी की निम्नलिखित गतिविधियों की सूचना दी:

a) उसने रुपये की मांग की थी। प्लाटून के पास मौजूद अधिशेष निर्माण भंडार के बदले कमांडर 367 आरएमप्लाटून (कनबल) से 15000;

बी) उसने 367 प्लाटून, गुंड डिटैचमेंट के अधीक्षक बीआर-आई एचएल मीना से बैरल के साथ 100 लीटर एचएसडी (हाई स्पीड डीजल) लिया था और उसके बाद बैरल के साथ इसे 1800/- रुपये में एक नागरिक को बेच दिया था, और यह आरोप था जिस वाहन में वह यात्रा कर रहा था उसके चालक द्वारा आरोप लगाया गया; ग) उसने अधिशेष निर्माण की सूचना नहीं देने के लिए अधीक्षक बीआर-द्वितीय संजय कुमार, 385 आरएम प्लाटून से 6000/- रुपये की उगाही की थी। पलटन द्वारा आयोजित सामग्री; घ) उसने 118 आरसीसी (जीआरईएफ) पर क्यूएम से दो स्टील हथौड़ों के साथ एक कोट/परखा लिया था।

2. इन रिपोर्टों के आधार पर, मुख्य अभियंता, प्रोजेक्ट बीकन ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया, जिसने इन आरोपों की जांच की और निष्कर्ष निकाला। प्रतिवादी बिना अधिकार के किए गए उपरोक्त चार कृत्यों में से दो के लिए दोषी था: पहला, 30 नवंबर, 2001 को बीआर-आई एचएल मीना से 100 लीटर एचएसडी की मांग करना और उसे एक नागरिक को बेचना, और दूसरा, 5 दिसंबर, 2001 को मांग करना और लेना। एक कोट/परखा और दो पत्थर तोड़ने वाले स्टील के हथौड़े। मुख्य अभियंता आंशिक रूप से जांच न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत हुए और उपरोक्त दो कृत्यों के लिए प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्देश दिया। प्रतिवादी पर दो संबंधित कृत्यों के लिए दो मामलों में मुकदमा चलाया गया और सेना अधिनियम, 1950 की धारा 53 (ए) के तहत जबरन वसूली करने का आरोप लगाया गया। साक्ष्य का सारांश नियम 23, सेना नियमों के तहत दर्ज किया गया था और प्रतिवादी पर 11.04.2002 को लेफ्टिनेंट कर्नल सीएम कुमार ऑफिसर कमांडिंग, (ओसी) की अध्यक्षता में समरी कोर्ट मार्शल (एससीएम) द्वारा मुकदमा चलाया गया था। प्रतिवादी

ने दोनों आरोपों में दोष स्वीकार किया। एससीएम की सुनवाई में, अभियोजन पक्ष के दो गवाहों से पूछताछ की गई, जिनमें से दोनों प्रतिवादी ने जिरह करने से इनकार कर दिया। प्रतिवादी ने न तो अपने बचाव में कोई बयान दिया, न ही बचाव में कोई गवाह पेश किया। अंततः उन्हें "नाइक" के पद में कटौती की सज़ा दी गई। इसके बाद, पुनर्विचार के कारणों से, 'समीक्षा प्राधिकारी' ने कथित तौर पर अधिनियम की धारा 162 के तहत कार्य करते हुए, एससीएम की 'समीक्षा' करते हुए, इसे अलग रख दिया, "आरोप के गलत निर्धारण और साक्ष्य के सारांश में सबूतों की लापरवाहीपूर्ण रिकॉर्डिंग के कारण" . यह हस्तक्षेप नियम 115 के अनुरूप प्रमाणन के दायरे में है। चूंकि यह उप न्यायाधीश-महाधिवक्ता है जिसने ये टिप्पणियां की हैं और रिकॉर्ड इस बात को प्रमाणित नहीं करते हैं कि उनकी राय/टिप्पणी को स्वीकार किया गया था या अनुमोदित किया गया था। 'समीक्षा प्राधिकारी' द्वारा, जिसे वैधानिक रूप से धारा 162 में सूचीबद्ध वरिष्ठ रैंकिंग अधिकारी होना चाहिए, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में 'समीक्षा' नहीं हुई थी। यह मूलतः उप न्यायाधीश-महाधिवक्ता द्वारा सत्ता का कब्ज़ा है।नियम 133 में निस्संदेह इस अधिकारी का उल्लेख है, लेकिन उसकी भूमिका धारा 162 के अनुसरण में इनसे निपटने के लिए अधिकृत अधिकारी को समरी कोर्ट मार्शल की कार्यवाही अग्रेषित करने तक ही सीमित है। अधिक से अधिक उप न्यायाधीश-महाधिवक्ता प्राधिकृत अधिकारी को अग्रेषित करते समय समरी कोर्ट मार्शल की कार्यवाही में अपनी राय जोड़ सकते हैं। यह इस तथ्य से पूरी तरह से स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय को उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड में "निर्धारित अधिकारी" का कोई आदेश नहीं है जो कार्यवाही को रद्द कर दे या एससीएम द्वारा लगाई गई किसी अन्य सजा को कम कर दे। हमें यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि उप न्यायाधीश-महाधिवक्ता ने बिना किसी वैधानिक अधिकार के, सजा को रद्द करने या कम करने के बजाय, यह राय दी है कि समरी कोर्ट मार्शल को ही अलग रखा जाना चाहिए और अभियुक्त/प्रतिवादी को दोषी ठहराया जाना चाहिए। मुकदमे के सभी परिणामों से छुटकारा। अपनी स्वयं की राय के

बिल्कुल विपरीत, उप न्यायाधीश-महाधिवक्ता ने हेराफेरी के निष्कर्ष को वापस कर दिया है और यह सजा दी है कि अभियुक्त/प्रतिवादी का आचरण उसके प्रतिधारण को खराब कर देता है। सेवा को अवांछनीय बताया। इसने निर्धारित किया कि यद्यपि कोर्ट मार्शल का संचालन करने वाले अधिकारी ने नियम 116(4) के तहत दोषी होने की दलील दर्ज की, लेकिन साक्ष्य के सारांश में प्रतिवादी के बयान के अवलोकन ने इस रिकॉर्डिंग को गलत साबित कर दिया; उसमें, दूसरे आरोप के अनुसार, प्रतिवादी ने यह कहते हुए आरोप का विरोध किया था कि उसने केवल एक हथौड़े की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया था जिसे सर्दियों के अंत में वापस किया जाना था। बाद में हथौड़े का निरीक्षण करने पर, प्रतिवादी को पता चला कि उसके द्वारा अनुरोध किए गए हथौड़े के बजाय अंदर दो हथौड़े भरे हुए थे।

3. समीक्षा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने का दावा करने वाले उप न्यायाधीश-महाधिवक्ता ने इस विसंगति पर विचार करते हुए राय दी कि "मुकदमा चलाने वाले अधिकारी को एआर 116 (4) के तहत रिकॉर्ड में बदलाव करना चाहिए था और 'दोषी नहीं' होने की दलील दर्ज करनी चाहिए थी। दोनों आरोपों का सम्मान किया गया, और तदनुसार मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ाई गई। उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन न करना, मौजूदा मामले में, एक गंभीर कानूनी कमजोरी है, जिससे एससीएम कार्यवाही रद्द की जा सकती है। इसलिए, आरोपी द्वारा दोषी होने की दलीलों के बावजूद, निष्कर्ष, दोनों आरोपों पर दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेरी सुविचारित राय है कि, सारांश कोर्ट मार्शल कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है, और मैं आपको तदनुसार सलाह देता हूं। यदि आप सहमत हैं, तो निम्नलिखित होगा कार्यवाही के पृष्ठ "जे" पर रिकॉर्ड करने के लिए आपके लिए उपयुक्त मिनट: - 'मैंने कार्यवाही को रद्द कर दिया। मैं निर्देश देता हूं कि आरोपी को मुकदमे के सभी परिणामों से मुक्त किया जाए।"रिकॉर्ड से यह पता नहीं चलता है कि इस सलाह पर कार्यवाही की गई थी .

4. इसी गतिरोध में कुछ ही समय बाद प्रतिवादी को एक कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी अपने कार्यकाल के दौरान अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया गया था। प्रतिवादी पर उन्हीं कथित कृत्यों के लिए अनुशासनहीनता के कृत्यों का आरोप लगाया गया था जो पूर्व में जबरन वसूली के दो अपराधों के लिए उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्यवाही का विषय थे। प्रतिवादी को यह बताया गया कि सेना में उनकी निरंतर उपस्थिति संभवतः अनुशासन बनाए रखने के लिए हानिकारक होगी और इसलिए सेवा में उनका प्रतिधारण अवांछनीय माना गया था। प्रतिवादी को यह कारण बताना आवश्यक था कि सेना नियम 13 के प्रावधानों के तहत उसकी सेवा क्यों समाप्त नहीं की जानी चाहिए। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया है कि उसने इस नोटिस का जवाब दिया है लेकिन यह रिकॉर्ड पर नहीं है। प्रतिवादी को कथित तौर पर मौखिक रूप से बताया गया था कि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और नियम 13 के तहत 05.02.2003 को डिस्चार्ज प्रमाणपत्र जारी किया गया था।

5. प्रतिवादी ने इस डिस्चार्ज के खिलाफ एक सीडब्ल्यूपी दायर की, जिसमें उन्हीं कथित कृत्यों के खिलाफ इसके जारी होने की वैधता को खारिज कर दिया गया था जो पहले से ही कोर्ट मार्शल कार्यवाही के अधीन थे। प्रतिवादी ने संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21 और 311 पर भरोसा किया, और उससे छुटकारा पाने के लिए सेना अधिकारियों द्वारा अपनाई गई "अवैध प्रक्रिया और शॉर्ट कट विधि" के खिलाफ दावा किया। अपीलकर्ताओं ने प्रारंभिक बिंदु के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष अपने उत्तर में कहा कि प्रतिवादी के किसी भी अधिकार, मौलिक अधिकार की तो बात ही छोड़ दें, का उल्लंघन नहीं किया गया है। इस प्रकार उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार अनुचित होने के कारण, अपीलकर्ताओं ने प्रारंभिक बर्खास्तगी की प्रार्थना की उस बिंदु पर. अपीलकर्ताओं ने इस बात से इनकार किया कि प्रतिवादी को जबरन वसूली के अपराध के लिए आरोपमुक्त कर दिया गया है; बल्कि, प्रतिवादी के कदाचार ने नैतिक अधमता और घोर अनुशासनहीनता को जन्म दिया, जिसका मतलब था कि सेना में उसकी

निरंतर सेवा अब वांछनीय नहीं मानी गई। अपीलकर्ताओं ने प्रचार किया कि प्रतिवादी, "सिविल सेवक" नहीं होने के कारण, अनुच्छेद 311 के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस मामले में निर्वहन प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया था। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और कारण बताओ नोटिस को अस्थिर बताते हुए रद्द कर दिया। न्यायालय ने इस आधार पर निष्कर्ष निकाला कि कारण बताओ नोटिस बिल्कुल उन्हीं आरोपों पर आधारित था, जो कोर्ट मार्शल में चले थे, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी को बरी कर दिया गया था। कोर्ट ने अपीलकर्ताओं द्वारा कोर्ट मार्शल का विषय होने वाले जबरन वसूली, और कारण बताओ नोटिस और डिस्चार्ज का विषय होने वाले कदाचार और अनुशासनहीनता के बीच के अंतर को स्वीकार नहीं किया। फिर भी, उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष प्रतिवादी को कायवाही से नहीं रोका। "आरोपों के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ कानून के अनुसार कोई भी विभागीय कार्यवाही करना।" यह वह निर्णय है जो हमारी जांच के लिए हमारे सामने है।

6. तथ्यात्मक टेपेस्ट्री को पिरोया गया है, हम मुख्य रूप से इस बात से जूझ रहे हैं कि क्या अपीलकर्ता कानूनी रूप से नोटिस जारी कर सकते थे और प्रतिवादी को कदाचार और अनुशासनहीनता के लिए बरी कर सकते थे, जब कथित कृत्यों का एक ही सेट पहले अपराध के रूप में आरोपित किया गया था और कोर्टमार्शल के माध्यम से रखा गया था। जिसमें अंततः प्रतिवादी को बरी कर दिया गया। दूसरे शब्दों में, जिस कानूनी गुत्थी पर हमें विचार करना है वह सेना के किसी सदस्य के खिलाफ समरी कोर्ट मार्शल कार्यवाही के बाद उसी या इसी तरह के आरोपों को खारिज किए जाने के बाद उसकी डिस्चार्ज जांच शुरू करने के औचित्य पर है। आक्षेपित निर्णय के संदर्भ में, सेना/भारत संघ (यूओआई), हमारे समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा पारित डिस्चार्ज ऑर्डर को रद्द कर दिया गया है। हालाँकि समान आरोपों के संबंध में विभागीय कार्रवाई की शुरुआत पर रोक या रोक नहीं लगाई गई है। अपीलकर्ताओं ने पुरजोर ढंग से तर्क दिया

कि उच्च न्यायालय ने आरोपित आरोप मुक्त करने के आदेश को रद्द करके गलती की है। स्पष्ट रूप से, प्रतिवादी ने विभागीय जांच शुरू करने के लिए यूओआई को छुट्टी देने पर आपत्ति नहीं जताई है। हालाँकि, हमारे सामने यह जोरदार तर्क दिया गया है कि एससीएन दिनांक 31.10.2002 दोहरे खतरे से ग्रस्त है और इसलिए, डिवीजन बेंच द्वारा सही ढंग से रद्द कर दिया गया है। जब आपराधिक आरोप भी लगाए गए हों तो विभागीय कार्यवाही शुरू होने या जारी रहने का रहस्य हमेशा मुश्किल होता है। लेकिन एक ऐसा जलविभाजक है जिसे पर्याप्त परिश्रम के बावजूद भी पहचाना जा सकता है।

7. हम तुरंत दोहरे खतरे की अवधारणा का विश्लेषण करेंगे, विशेषकर हमारे विश्व में फैले देशों के संविधानों की पृष्ठभूमि में। अमेरिकी संविधान के पांचवें संशोधन में वादा किया गया है कि - "किसी भी व्यक्ति को किसी पूंजी, या अन्यथा कुख्यात अपराध के लिए जवाब देने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि ग्रैंड जूरी की प्रस्तुति या अभियोग पर, भूमि या नौसेना बलों से उत्पन्न मामलों को छोड़कर, या मिलिशिया में, जब युद्ध या सार्वजनिक खतरे के समय वास्तविक सेवा में हो; न ही किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार जीवन या अंग को खतरे में डालने के लिए मजबूर किया जाएगा; न ही किसी आपराधिक मामले में मजबूर किया जाएगा अपने ख़िलाफ़ किसी गवाह को, क़ानून की उचित प्रक्रिया के बिना, जीवन, स्वतंत्रता, या संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा; न ही उचित मुआवजे के बिना, निजी संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिए लिया जाएगा।" इस सुरक्षा को तीन पहलुओं की स्वीकृति के रूप में माना गया है: i) ऑट्रेफॉइस बरी ii) ऑट्रेफॉइस दोषी iii) कई दंडों के खिलाफ संरक्षण। हम संक्षेप में जॉन हडसन बनाम यूनाइटेड स्टेट्स 522 यूएस 93 (1997) का उल्लेख करेंगे जहां अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे खतरे के मापदंडों पर प्रकाश डाला है। दूसरा, दक्षिण अफ़्रीका गणराज्य (1996) के संविधान के अनुच्छेद 35(3)(एम) में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति पर "किसी ऐसे कार्य या चूक के संबंध में अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा जिसके लिए वह व्यक्ति पहले भी दोषी ठहराया जा चुका है।" बरी

कर दिया गया या दोषी ठहराया गया"। हर्ड, कनाडाई संविधान के अधिकारों के चार्टर की धारा 11 (एच) में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया गया है, उसे यह अधिकार है कि "यदि वह अंततः अपराध से बरी हो जाता है, तो उसके लिए दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और, यदि अंततः दोषी पाया जाता है और दंडित किया जाता है अपराध के लिए, उसके लिए दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा"। चौथा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (आईसीसीपीआर, 1966) के अनुच्छेद 14 (7) में कहा गया है: "कोई भी उस अपराध के लिए दोबारा मुकदमा चलाने या दंडित होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जिसके लिए उसे पहले ही अंततः दोषी ठहराया जा चुका है या उसके अनुसार बरी कर दिया गया है।" प्रत्येक देश के कानून और दंड प्रक्रिया के साथ"। पांचवां, पाकिस्तान के संविधान, 1973 का अनुच्छेद 13 इस प्रकार है - दोहरी सजा और आत्म-दोषारोपण के खिलाफ सुरक्षा? किसी भी व्यक्ति- (ए) पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा; या (बी) जब किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो उसे अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर किया जाएगा।

8. एक अलग रास्ते पर चलते हुए, यूके क्रिमिनल जस्टिस एक्ट, 2003 ने ऑट्रेफॉइस दोषी के संचालन को संशोधित किया है, जिसके भाग 10 में 'नए और सम्मोहक' साक्ष्य की स्थिति में, उसमें निर्धारित गंभीर अपराधों के मामलों में पुन: सुनवाई की अनुमति दी गई है। अर्हक अपराध के संबंध में बरी किए गए व्यक्ति के विरुद्ध। इस क़ानून का न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई राज्यों क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, तस्मानिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया में कानूनों द्वारा अनुकरण किया गया है।

9. भारत का संविधान दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल करने के संदर्भ में एक विरोधाभासी पाठ्यक्रम पेश करता है जिसमें अनुच्छेद 20(2) कहता है कि - "किसी भी

व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा।" अन्य देशों में दी गई संवैधानिक सुरक्षाओं से इस भिन्नता ने हमें 'संविधान सभा की बहसों' के माध्यम से जांच करने के लिए प्रेरित किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अधिक प्रबल ऑटोरेफोइस को बरी करने के बजाय दोषी ठहराए गए ऑट्रेफॉइस की स्थिति हमारे संविधान के प्रारूपकारों द्वारा नियुक्त की गई थी। ये बहसें इस तथ्य की गवाही देती हैं कि यह वास्तव में चिंतन और इरादा था। मूल प्रस्ताव था - "किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा"। एक प्रस्तावित संशोधन जिसमें "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 द्वारा प्रस्तावित के अलावा अन्यथा" शब्द जोड़ने की मांग की गई थी, लेकिन इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। श्री नज़ीरुद्दीन अहमद द्वारा दिया गया सुझाव यह था कि "सिद्धांत यह होना चाहिए कि किसी व्यक्ति पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, यदि उसे सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा बरी कर दिया जाता है या दोषी ठहराया जाता है, जबकि दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रभावी होती है... एक आदमी बरी किए गए व्यक्ति पर भी दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।" (2 दिसम्बर 1948) अगले दिन, श्री टी.टी. कृष्णमाचारी के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया गया, जिससे 'ऑट्रेफॉइस बरी' के लिए मौत की घंटी बज गई और अनुच्छेद 20(2) की ओर अग्रसर हुआ, जो आज मौजूद है। श्री टी.टी. एफ कृष्णमाचारी (मद्रास: जनरल):

> "उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष मुझे जो बात रखनी है वह तुलनात्मक रूप से संकीर्ण है। इस अनुच्छेद 14 में, खंड (2) इस प्रकार है: 'किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा 'इस सदन के कई सदस्यों ने मुझे बताया है कि इसका असर संभवत: उन मामलों पर पड़ सकता है, जहां सरकारी अधिकारी के मामले में, जिस पर विभागीय कार्यवाही की

गई हो और सजा दी गई हो, उस पर फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और दंडित नहीं किया जा सकता। यदि उसने कोई आपराधिक अपराध किया था; या, इसके विपरीत, यदि किसी सरकारी अधिकारी पर मुकदमा चलाया गया था और उसे अदालत द्वारा कारावास या जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, तो यह सरकार को उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से रोक सकता है। हालांकि मुद्दा एक संकीर्ण और एक है जो यह व्याख्या करने में सक्षम है कि क्या मौलिक अधिकारों में इस विशेष खंड में यह प्रावधान सरकार के अपने अधिकारियों के संबंध में आचरण और अनुशासन के नियमों के तहत कार्य करने के विवेक को प्रभावित करेगा, मुझे लगता है, जब हम एक विशेष प्रकार की कार्यवाही पर प्रतिबंध लगा रहे हैं , बात को और स्पष्ट कर देना बेहतर है।

मैं मानता हूं कि संशोधन पेश करने में अब मुझे काफी देर हो गई है। मैं इस खंड को इस प्रकार कहना चाहूंगा: 'किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा।" यदि मेरे माननीय मित्र डॉ. अंबेडकर इन शब्दों को जोड़ने को स्वीकार करेंगे

'दंडित' शब्द से पहले मुकदमा चलाया गया और यदि आप, श्रीमान, और सदन उसे ऐसा करने की अनुमति दे, तो यह न केवल एक बुद्धिमानी होगी बल्कि यह भविष्य की सरकारों के लिए बहुत सारी परेशानियों से बचाएगा। . यह सदन के समक्ष रखने योग्य सुझाव है। यह सदन पर निर्भर है कि वह जिस भी तरीके से उचित समझे, उससे निपटे।"

10. यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि आधुनिक न्यायशास्त्र वर्तमान में वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के संदर्भ में संसदीय बहसों के अवलोकन में आंशिक है, हालांकि पहले इस अभ्यास को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। आर.एस नायक बनाम ए.आर अंतुले (1984) 2 एससीसी 183 और हल्दीराम भुजियावाला बनाम आनंद कुमार दीपक कुमार (2000) 3 एससीसी250 में संविधान पीठ के विश्लेषण का उल्लेख करना पर्याप्त है; और विशेष रूप से समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1997) 8 एससीसी 191, जहां संसदीय बहस का अध्ययन इस न्यायालय द्वारा किया गया था। यह बहस से परे प्रतीत होता है कि हमारे संविधान के निर्माता ऑट्रेफॉइस बरी और ऑट्रेफॉइस दोषी की भिन्न और असमान अवधारणाओं के प्रति पूरी तरह से सचेत थे और उन्होंने जान-बूझकर दोहरे खतरे के सिद्धांत को केवल अभियोजन पक्ष तक सीमित रखने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई। कानून के इस पहलू पर मकबूल हुसैन बनाम बॉम्बे राज्य 1953 एससीआर 730 मामले में संविधान पीठ द्वारा पहले ही सावधानीपूर्वक विचार किया जा चुका है, और हम उसमें से प्रासंगिक अंश निकालने से बेहतर कुछ नहीं कर सकते हैं:

> "7. अनुच्छेद 20(2) में जिस मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है, वह "ऑट्रेफॉइस दोषी" या "दोहरे खतरे" के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। उस सिद्धांत की जड़ें इंग्लैंड के आम कानून की अच्छी तरह से स्थापित रूई में पाई जाती हैं "जहां किसी व्यक्ति को सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, सजा उसी के लिए आगे की सभी आपराधिक कार्यवाही पर रोक है। अपराध"। (प्रति चार्ल्स, जे.इन रेग बनाम माइल्स)। इसी प्रभाव के लिए प्राचीन कहावत है "निमो बिस देबेट पुनीरी प्रो यूनो डी/इक्टो", जिसका अर्थ है कि किसी को भी एक अपराध के लिए दो बार दंडित

नहीं किया जाना चाहिए या जैसा कि कभी-कभी लिखा जाता है "प्रो एडेम कॉसा", अर्थात, उसी कारण से।

11. ये वे सामग्रियां थीं जिन्होंने अनुच्छेद 20(2) में दी गई मौलिक अधिकार की गारंटी की पृष्ठभूमि तैयार की। इसने अपने दायरे में "ऑट्रेफॉइस दोषी" की याचिका को शामिल किया जैसा कि ब्रिटिश न्यायशास्त्र में जाना जाता है या दोहरे खतरे की याचिका जैसा कि अमेरिकी संविधान में जाना जाता है, लेकिन यह प्रावधान करके इसे सीमित कर दिया कि न केवल अभियोजन होना चाहिए बल्कि पहली बार में सजा भी होनी चाहिए। एक ही अपराध के लिए दूसरे अभियोजन और सजा में बाधा के रूप में कार्य करने के लिए।

12. अनुच्छेद 20(2) में "न्यायालय या न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष" शब्द नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर ऊपर बताई गई पूरी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाए तो यह स्पष्ट है कि किसी नागरिक द्वारा अनुच्छेद 20(2) के संरक्षण को लागू करने के लिए किसी अदालत के समक्ष उसी अपराध के संबंध में अभियोजन और सजा होनी चाहिए। एक न्यायाधिकरण, जिसे कानून द्वारा विवाद के मामलों को शपथ पर साक्ष्य के आधार पर न्यायिक रूप से तय करने की आवश्यकता होती है, जिसे प्रशासित करने के लिए इसे कानून द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए, न कि किसी न्यायाधिकरण से पहले जो एक विभागीय या प्रशासनिक जांच पर विचार करता है, भले ही एक क़ानून द्वारा स्थापित किया गया हो, लेकिन आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शपथ पर दिए गए कानूनी साक्ष्य पर. अनुच्छेद 20 की मूल शब्दावली और उसमें प्रयुक्त शब्दः - "दोषी ठहराया

गया", "अपराध के रूप में आरोपित कार्य का कमीशन", "दंड के अधीन होना", "अपराध का कमीशन", "मुकदमा चलाना, और दंडित करना, किसी भी आरोपी पर मुकदमा चलाना और दंडित करना" अपराध, यह संकेत देगा कि उसमें विचार की गई कार्यवाही कानून की अदालत या न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष आपराधिक कार्यवाही की प्रकृति की है और इस संदर्भ में अभियोजन का मतलब कानून की अदालत या न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष आपराधिक प्रकृति की कार्यवाही की शुरुआत या शुरुआत होगी। क़ानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार न्यायाधिकरण जो अपराध बनाता है और प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।

11. हमारे संविधान में बताए गए दोहरे खतरे की इस व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, बिहार राज्य बनाम मुराद अली खान (1988) 4 एससीसी 655 में दो जजों की बेंच द्वारा पारित आदेश कानून को सही ढंग से स्पष्ट नहीं करता है। क्योंकि यह दृष्टिकोण संविधान पीठ के आदेश के विपरीत है, जिसे पीठ के ध्यान में नहीं लाया गया।

12. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 5 वें संशोधन के तहत दोहरे खतरे के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा को आकर्षित करने के प्रयोजनों के लिए क्रमिक "दंड" के गठन के बारे में व्यापक रूप से चर्चा की है। जॉन हडसन बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालय, 522 यू.एस. 93 (1997), नागरिक दंड और कार्यवाही तथा आपराधिक दंड और अभियोजन के बीच अंतर की पुष्टि की, और माना कि पांचवां संशोधन केवल आपराधिक प्रकृति के दो (या अधिक) क्रमिक दंड या अभियोजन को प्रतिबंधित करता है, और नागरिक दंड या कार्यवाही को या तो पूर्ववर्ती या बाद की अनुमति देता है। आपराधिक मुकदमा या सजा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले में, जॉन हडसन

फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ टिपटन और फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ हैमन के अध्यक्ष थे, और उन्होंने अपने पद का उपयोग बैंक स्टॉक को पुनः प्राप्त करने के लिए किया था, जिसका उपयोग उन्होंने डिफॉल्ट किए गए ऋणों पर संपार्श्विक के रूप में किया था। अन्य पक्षों को बैंक ऋणों की श्रृंखला। जांच करने पर मुद्रा नियंत्रक कार्यालय (ओसीसी) ने पाया कि ऋण कई बैंकिंग प्रतिमानों और नियमों का उल्लंघन करके दिए गए थे। ओसीसी ने उल्लंघन के लिए हडसन पर जुर्माना लगाया और उसे प्रतिबंधित कर दिया। बाद में, उन्हीं घटनाओं से जुड़े उल्लंघनों के लिए उन्हें संघीय जिला न्यायालय में आपराधिक अभियोग का सामना करना पड़ा। हडसन ने आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि अभियोग ने 5 वें संशोधन के डबलजेओपार्डी खंड का उल्लंघन किया है। डेवररूलिंग युनाइटेड स्टेट्स बनाम हेल्पर, 490 यू.एस. 436 (1989), जिसमें न्यायालय नेहडसन के मामले के समान परिस्थितियों में होने वाली क्रमिक कार्यवाही को असंवैधानिक करार देते हुए, हडसन की अदालत ने संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम वार्ड, 448 यू.एस. 242 (1980) में विशेष क्रमिक सजा की "सिविल" और "आपराधिक" प्रकृति के बीच स्थापित अंतर की पुष्टि की।). अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार हडसन के मामले में माना कि दोहरा खतरा खंड ने उसके बाद के आपराधिक मुकदमे को नहीं रोका, क्योंकि ओसीसी प्रशासनिक कार्यवाही नागरिक थी, आपराधिक नहीं। अन्य बातों के साथ-साथ, सज़ा की नागरिक प्रकृति का पता धन दंड क़ानूनों द्वारा उनके प्रतिबंधों को "सिविल" के रूप में व्यक्त करने के संदर्भ में लगाया गया था। यह संदर्भ निस्संदेह वर्तमान अपील में दोहरे ख़तरे के प्रश्न के समाधान को आसान बनाता है। जैसा कि पहले विस्तृत किया गया है, अनुच्छेद 20(2) ऐसा नहीं करता है। इसके भीतर ऑट्रेफॉइस बरी के सिद्धांत को आत्मसात करें। पाँचवाँ संशोधन सुरक्षा उपाय, हालाँकि यह ऑट्रेफ़ोइस बरी और ऑटोरेफ़ोइस दोषी दोनों को मानता है, अभियोजन में बरी होने के बाद भी नागरिक दंड को प्रतिबंधित करने के लिए इसकी व्याख्या की जा सकती थी, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं पाया। एक फोर्टियोरी अनुच्छेद 20(2), जो "मुकदमा चलाने और

दंडित करने" पर विचार करता है और इस प्रकार ऑटोरेफॉइस बरी के सचेत बहिष्कार को दर्शाता है, स्पष्ट रूप से यह मानता है कि निर्धारित क्रमिक सजा एक आपराधिक चरित्र की होनी चाहिए। यह निर्विवाद रूप से इस बात का अनुसरण करता है कि विभागीय या अनुशासनात्मक कार्यवाही, भले ही आयाम में दंडात्मक हो, अनुच्छेद 20(2) द्वारा गैरकानूनी नहीं होगी।

13. आर. पी. कपूर यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 1964 एससी 787 में संविधान पीठ के समक्ष प्रश्न यह था कि याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही लंबित होने के कारण निलंबित कर दिया गया था, जिसे संविधान के अनुच्छेद 314 के आधार पर चुनौती दी गई थी। इस प्रकार, यह निर्णय हमारे समक्ष मौजूद कानूनी विवाद के समाधान के लिए अधिक प्रासंगिक नहीं है, इन टिप्पणियों को छोड़कर कि "यदि आपराधिक आरोप के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि होती है, तो लोक सेवक को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, यहां तक कि बरी होने की स्थिति में भी कार्यवाही तब हो सकती है जब बरी करना सम्मानजनक के अलावा अन्य हो।" हालाँकि, कानून के इस पहलू पर हमें पुलिस उप-जनरल बनाम एस समुथिराम (2013) 1 एससीसी 598 के हालिया फैसले से आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सभी प्रमुख उदाहरणों पर एक व्यापक चर्चा शामिल है। इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है, और हम आदरपूर्वक सही ढंग से सोचते हैं कि आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी कर्मचारी को बरी करने से विभागीय कार्यवाही पर स्वचालित रूप से और निर्णायक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे पहले, यह दोनों में सबूत की असमान डिग्री के कारण है, अर्थात् आपराधिक अभियोजन में उचित संदेह से परे सिविल या विभागीय पूछताछ में प्रबल सबूत के विपरीत। दूसरे, आपराधिक अभियोजन संबंधित विभाग के नियंत्रण में नहीं है और दोषमुक्ति घटिया जांच या साक्ष्यों को लापरवाही से आत्मसात करने, या मुकदमे के संचालन में लापरवाही आदि का परिणाम हो सकता है। तीसरा, आपराधिक अभियोजन में बरी होने से विपरीत परिणाम पर रोक

लग सकती है विभागीय जांच में निष्कर्ष, यदि पूर्व एक निष्क्रिय फैसले के विपरीत एक सकारात्मक निर्णय है, जो तकनीकी कमजोरियों पर आधारित हो सकता है। दूसरे शब्दों में, आपराधिक न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि अभियुक्त निर्दोष है, न कि केवल यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वह उचित संदेह से परे दोषी साबित नहीं हुआ है।

14. वास्तव में, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मामला निष्क्रिय श्रेणी में आता है क्योंकि प्रतिवादी को तकनीकी कारणों से गलत तरीके से छोड़ दिया गया है, और वह भी, जेएजी शाखा की विशेष नहीं तो बहुत ही अविश्वसनीय और बहस योग्य राय पर। 11 अप्रैल, 2002 को समरी कोर्ट मार्शल आयोजित किया गया था जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल पी. भूटानी 'अभियुक्त के मित्र' के रूप में उपस्थित थे, जेसी एम. सब केसी मनोचा दुभाषिया के रूप में उपस्थित थे। आक्षेप के समय अभियुक्त/प्रतिवादी ने दोनों आरोपों का दोष स्वीकार किया। न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि प्रतिवादी उसे आरोपों का अर्थ समझाया गया था और वह उन्हें अपने अपराध स्वीकार करने के प्रभाव और परिणामों के बारे में भी समझता था। साक्ष्य के सारांश में चार गवाहों से पूछताछ की गई, एक से जिरह की गई और प्रतिवादी ने अन्य के लिए इस अवसर को अस्वीकार कर दिया। उचित सावधानी बरतने की सलाह देने के बाद अभियुक्त/प्रतिवादी ने एक विस्तृत बयान दिया। समीक्षा अधिकारी की राय थी कि सेना नियम 116(4) में 'दोषी' याचिका को 'दोषी नहीं' में बदलने की आवश्यकता थी, जो इस अप्रमाणित और अस्थिर निष्कर्ष पर आधारित था कि प्रतिवादी ने पूर्व के प्रभाव को नहीं समझा था। इस निष्कर्ष के आधार पर, उनकी सिफारिश 'नाइक के पद में कमी' की कार्यवाही और सजा को रद्द करने और यह भी निर्देश देने की थी कि आरोपी को मुकदमे के सभी परिणामों से मुक्त कर दिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि, समीक्षा करने वाले प्राधिकारी ने यह भी कहा: "उक्त कथन के बावजूद, आरोप के गलत निर्धारण और साक्ष्य के सारांश में साक्ष्य की अपर्याप्त रिकॉर्डिंग के कारण, साक्ष्य से पता चलता

है कि आरोपी ने सीएमपी के सदस्य के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और विभिन्न वस्तुओं का दुरुपयोग किया। इसलिए, मेरी राय में, उसका आचरण उसे सेवा में बनाये रखने को अवांछनीय बनाता है। आप तदनुसार सेना नियम, 13 के प्रावधानों के तहत प्रशासनिक निर्वहन के लिए उसके मामले को आगे बढ़ाने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। यह इस पृष्ठभूमि में है कि हम यह राय रखना अतार्किक मानते हैं कि प्रतिवादी ने सम्मानजनक बरी कर दिया है। नतीजतन, क्या दोहरे खतरे के सिद्धांत या सेटिंग पर निर्भरता पर उसकी सज़ा के अलावा, विभागीय या अनुशासनात्मक कार्यवाही को वर्जित नहीं माना जाना चाहिए। विडंबना और विरोधाभासी रूप से, हम टिप्पणी कर सकते हैं, प्रतिवादी को कोर्ट मार्शल में निष्कर्षों को अलग करके कहीं अधिक कठोर कार्यवाही के प्रति संवेदनशील बना दिया गया है, जिसमें रैंक में कम होने की तुलनात्मक रूप से कम सजा से उसे सेवा से मुक्त कर दिया गया है।

15. सेना अधिनियम की धारा 121 में विशेष जांच की आवश्यकता है क्योंकि यह निर्दिष्ट करता है कि:

> 121. द्वितीय परीक्षण का प्रतिषेध. - जब इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को कोर्ट-मार्शल या आपराधिक अदालत द्वारा किसी अपराध से बरी कर दिया गया है या दोषी ठहराया गया है, या धारा 80, 83, 84 और 85 में से किसी के तहत निपटाया गया है, तो वह उत्तरदायी नहीं होगा उसी अपराध के लिए कोर्ट-मार्शल द्वारा दोबारा मुकदमा चलाया जाए या उक्त धाराओं के तहत निपटा जाए।

16. भाषा तुरंत इसे अनुच्छेद 20(2) से अलग करती है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से ऑट्रेफॉइस बरी और ऑट्रेफॉइस दोनों को कोर्ट-मार्शल या आपराधिक अदालतों द्वारा मुकदमे के लिए दोषी ठहराती है, लेकिन फिर इन्सुलेशन को केवल दूसरे कोर्ट-मार्शल या इसके तहत निपटारे तक सीमित कर देती है। सेना अधिनियम की धारा 80, 83,

84 और 85। धारा 121, 125 और 126 के संयुक्त अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि एक साथ कोर्ट-मार्शल और आपराधिक न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाने पर विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा, सेना अधिनियम आपराधिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों पर उचित रूप से अनिच्छुक है। हालांकि यह सवाल हमारे सामने नहीं उठता है, हम धारा 126 (2) के दायरे पर विचार करने से बच नहीं सकते हैं क्योंकि यह केंद्र सरकार को प्रधानता प्रदान करता है। इस बात का निर्धारण कि आपराधिक अदालत के फैसले की परवाह किए बिना कोर्ट मार्शल या आपराधिक अदालत के पास अपराधी की हिरासत होगी या नहीं। हालाँकि सेना अधिनियम की धारा 127 को सेना (संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा निरस्त कर दिया गया है, लेकिन यह उस दोष से ग्रस्त नहीं है जिसमें केंद्र सरकार के पास एक अपराधी द्वारा दूसरे/लगातार परीक्षण के लिए मंजूरी देने या देने से रोकने की शक्ति है। अदालत। पूर्ववर्ती प्रावधान इस प्रकार पढ़ा गया:-

> 127. (1) कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए गए या बरी किए गए व्यक्ति पर, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, उसी अपराध के लिए या समान तथ्यों पर फिर से आपराधिक अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है।
>
> 2) यदि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत कोर्ट-मार्शल द्वारा सजा सुनाई गई है या धारा 80, 83,84 या 85 में से किसी के तहत दंडित किया गया है, तो बाद में उसी अपराध के लिए, या समान तथ्यों पर एक आपराधिक अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जाता है और दोषी ठहराया जाता है, तो वह अदालत सज़ा देते समय, उस सज़ा का ध्यान रखना होगा जो वह उक्त अपराध के लिए पहले ही भुगत चुका है।"

17. हालाँकि हमारे सामने यह प्रश्न भी नहीं उठता है कि आपराधिक प्रक्रिया, 1973 की धारा 300 निश्चित रूप से संविधान के अनुरूप नहीं हो सकती है क्योंकि यह ऑट्रेफ़ोइस बरी और ऑटोरेफ़ोइस दोषी दोनों पर विचार करती है, भले ही हमारे संविधान के प्रारूपकारों द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया हो। वह सुरक्षा केवल उत्तरार्द्ध के संबंध में उपलब्ध होगी। निःसंदेह सीआरपीसी व्यक्ति को व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है और इसी कारण से संविधान के अनुच्छेद 20(2) की कसौटी पर इसकी आलोचना नहीं की गई है। हमें फिर से श्री नज़ीरुद्दीन अहमद के भाषण की ओर ध्यान दिलाना चाहिए, जिन्होंने संविधान सभा को इसी स्थिति की याद दिलाई थी, अर्थात्, तत्कालीन मौजूदा सीआरपीसी में भी दोहरे खतरे के व्यापक मापदंडों की याद दिलाई थी और संविधान में भी ऐसा ही करने की वकालत की थी।

18. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाम मेजर धर्मपाल कुकरेती, 1985 (2) धारा 412 में तीन जजों की बेंच के फैसले पर विचार करने का यह उपयुक्त समय होगा, क्योंकि उस मामले में प्राप्त तथ्यों में कोर्ट मार्शल का निष्कर्ष शामिल है। इसकी पुष्टि नहीं की गई थी, जिससे सेना अधिनियम, 1950 की धारा 153 लागू हो गई, जिसमें कहा गया है कि किसी जनरल, डिस्ट्रिक्ट या समरी जनरल, कोर्ट-मार्शल का कोई भी निष्कर्ष या सजा तब तक वैध नहीं होगी, जब तक इसकी पुष्टि न हो जाए। यह न्यायालय था विचार यह है कि "सेना अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था जो पुनरीक्षण पर कोर्ट-मार्शल के निष्कर्ष की पुष्टि नहीं होने पर नए कोर्ट-मार्शल के आयोजन का अधिकार देता हो"। इसके बाद, सेना नियमों के नियम 14 को सेना प्रमुख को अनियंत्रित रूप से सक्षम बनाने वाला माना गया: (ए) बर्खास्त करना या (बी) हटाना या (सी) किसी भी अधिकारी को सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त करना।भले ही सम्मानजनक बरी के पहलू को कुकरेती में लागू नहीं किया गया था, यह तत्व सेना नियमों के तहत कार्यवाही करने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य रखने में भी प्रासंगिक रहा होगा। इसके अलावा, अनुच्छेद 20(2) किसी नए कोर्ट मार्शल की शुरुआत पर भी

रोक नहीं लगाता है, जैसा भी मामला हो। जिस मामले से हम वर्तमान में निपट रहे हैं, उसके विपरीत कुकरेती एक कमीशन अधिकारी थे। नियम 14 केंद्र सरकार की सहमति से उपर्युक्त कार्यवाही की अनुमति देता है, जबकि नियम 11, 12 और 13 में शामिल नियम सेना अधिनियम के तहत नामांकित प्रत्येक व्यक्ति की छुट्टी आदि से संबंधित है। हमें तुरंत सेना अधिनियम की धारा 20 को याद करना चाहिए जो एक कमीशन अधिकारी के अलावा, इस अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त करने या हटाने का अधिकार देता है।

19. उच्च न्यायालय के समक्ष लगाया गया कारण बताओ नोटिस स्पष्ट रूप से प्रासंगिक तालिका के अवशिष्ट खंड 13(3)(111)(V) का सहारा लेते हुए नियम 13 पर आधारित था, हमने सचेत रूप से इसके लिए 'सर्किटली' शब्द का उपयोग किया है। कारण कि अपीलकर्ता सेना अधिनियम की धारा 20 का सहारा ले सकते थे। हम यहां सावधानी का एक शब्द जोड़ सकते हैं - किसी विशेष कार्य को करने की शक्ति क़ानून में स्थित होनी चाहिए, और यदि क़ानून के तहत बनाए गए नियम किसी ऐसे कार्य का आदेश देते हैं जिस पर क़ानून द्वारा विचार नहीं किया गया है, तो यह अत्यधिक प्रत्यायोजन के दोष से ग्रस्त होगा और क्या इस मंच पर अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। संबंधित प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए, स्वयं प्रकट होने वाली असंख्य स्थितियों से विस्तार से निपटने के लिए नियम बनाए गए हैं। इसलिए, नियमों की व्याख्या इस तरीके से की जानी चाहिए जो उन्हें मूल क़ानून के अनुरूप बनाए रखे। हमारे अनुभव के आधार पर, हमें ऐसा लगता है कि सेना अधिकारी अक्सर सेना अधिनियम के दायरे को पूरी तरह समझे बिना ही सेना के नियमों में उलझे रहते हैं।

20. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम हरजीत सिंह संधू, 2001 (5) एससीसी 593 मामले में एक अन्य तीन जजों की बेंच ने कुकरेती पर विचार किया और फिर निष्कर्ष निकाला कि यदि कोर्ट मार्शल के फैसले की पुष्टि नहीं की जाती है, तो अनुशासनात्मक

कार्यवाही, चाहे बर्खास्तगी (या, के लिए) की जाए। उस मामले में, नियम 14(2) का सहारा लिया जा सकता है (एक निर्वहन) का सहारा इस न्यायालय द्वारा लिया गया था ताकि केंद्र सरकार या सेना प्रमुख को इस संतुष्टि पर पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके कि चूंकि अधिकारी पर मुकदमा चलाना अनुचित या अव्यवहारिक है। कोर्ट मार्शल, अधिकारी या संबंधित अधिकारी को या तो बर्खास्त करने, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए।

21. आक्षेपित निर्णय में कहा गया है कि "यद्यपि सारांश में समान आरोपों के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कोर्ट मार्शल कार्यवाही को अलग रखा गया है और याचिकाकर्ता सफल हो गया है, बाद में आरोपमुक्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस उन्हीं आरोपों पर निर्भर करता है याचिकाकर्ता, जिसे हमारे विचार में बरकरार नहीं रखा जा सकता है। उपरोक्त का परिणाम यह है कि आरोपमुक्त करने का आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसके द्वारा याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ रद्द किया जाता है। हालांकि, यह प्रतिवादी को कोई भी विभागीय कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा। कानून के अनुसार आरोपों के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ"। हम इन निष्कर्षों को कायम रखने में असमर्थ हैं। पहली बात तो यह है कि दूसरे कोर्ट मार्शल पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि यह सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर हो, आदि। दूसरे, जैसा कि कुकरेती में आयोजित किया गया है और संधू में अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि की गई है, जहां कोर्ट मार्शल का निर्णय विफल हो जाता है। पुष्टि प्राप्त करने के लिए, प्रभाव यह है कि यह नहीं माना जा सकता है कि वास्तव में, एक कोर्ट मार्शल समाप्त हो गया है और इसके अलावा, हमारी राय में, ताकि एक नए को रोक दिया जा सके। धारा 121 में निहित दोहरे खतरे के सिद्धांत में केवल उस स्थिति में दूसरे मुकदमे के निषेध को आधार बनाया गया है, जब पहले मुकदमे में सजा/दोषी ठहराया जाता है।

22. नियम 13 के तहत प्रतिवादी के खिलाफ जारी डिस्चार्ज प्रमाणपत्र दिलचस्प ढंग से डिस्चार्ज के समय उसके चरित्र को "अनुकरणीय" बताता है। यह रिकॉर्डिंग डिप्टी जज-एडवोकेट जनरल द्वारा गैरकानूनी, अलग करने के आदेश के निष्कर्षों के साथ बेहद असंगत है, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि प्रतिवादी को कदाचार के लिए बर्खास्त किया जा सकता है, सेना में आगे की सेवा के लिए अयोग्य होना, विभिन्न वस्तुओं का दुरुपयोग किया। यह असंगति नियम 13 के तहत मुक्ति की कार्यवाही को और अधिक बदनाम और अस्थिर बनाती है, जिसे हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं कि इसे अवशिष्ट प्रविष्टि के आधार पर सर्किट रूप से प्रयोग किया गया है, और सेना अधिनियम की बर्खास्तगी शक्तियों का अधिक्रमण किया गया है, जो निश्चित रूप से अगली कड़ी के रूप में प्रयोग योग्य हैं। असफल कोर्ट मार्शल कार्यवाही. नियम 12 के साथ पठित धारा 23 के तहत जारी किया गया डिस्चार्ज प्रमाणपत्र, डिस्चार्ज कार्यवाही का निर्णायक कदम है, इसलिए टिक नहीं सकता।

23. धारा 162 के तहत रद्द करने का प्रत्यक्ष आदेश जो रिकॉर्ड पर रखा गया है वह उप न्यायाधीश-महाधिवक्ता का आदेश है, लेकिन यह धारा 162 द्वारा परिकल्पित अधिकार नहीं है। धारा 162 के तहत किसी सक्षम अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश नहीं है धारा 162 के तहत समीक्षा कार्य के अभ्यास में गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही को रद्द करने का संकेत दिया गया है। अपीलकर्ताओं ने आदेश को वैध बनाने के लिए धारा 162 के साथ सेना अधिनियम के नियम 133 का लाभ उठाने का प्रयास किया है। नियम 133 कहता है:

> 133. कार्यवाहियों की समीक्षा.- सारांश कोर्ट-मार्शल की कार्यवाही, घोषणा के तुरंत बाद, निपटने के लिए अधिकृत अधिकारी को (कमांड के उप न्यायाधीश-महाधिवक्ता के माध्यम से) भेजी जाएगी धारा 162 के अनुसरण में उनके साथ, उनके द्वारा समीक्षा के बाद, उन्हें नियम

146 के उप-नियम (2) के अनुसार संरक्षण के लिए आरोपी व्यक्ति के दल में वापस कर दिया जाएगा।

नियम 133 उप न्यायाधीश-महाधिवक्ता को समीक्षा प्राधिकारी के रूप में सशक्त नहीं करता है, बल्कि इसे केवल एक अग्रेषण कार्य प्रदान करता है, नियम में कहा गया है कि उद्घोषणा पर एससीएम की कार्यवाही को धारा 162 के तहत सक्षम अधिकारी को अग्रेषित करने की आवश्यकता है, लेकिन केवल मूल रूप से प्रावधान है कि यह "उप न्यायाधीश-महाधिवक्ता के माध्यम से" होगा। इसे उपन्यायाधीश-महाधिवक्ता में धारा 162 के तहत समीक्षा प्राधिकारी की वैधानिक छूट को स्थापित करने के रूप में स्थानापन्न रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, हमारे द्वारा पहले ही यह राय दी जा चुकी है कि अलग-अलग सेटिंग "तकनीकी रूप से" हुई थी और इसे धारा 162 के संदर्भ में अनुमति नहीं दी गई थी।

24. हमें यह जोड़ना भी उचित लगता है कि यद्यपि उप न्यायाधीश-महाधिवक्ता (समीक्षा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाले) और सारांश कोर्ट मार्शल के बीच विसंगति थी, जिसके परिणामस्वरूप एक निरर्थक कोर्ट मार्शल प्रक्रिया हुई, अधिनियम का अवलोकन भी किया गया। रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों से पता चलेगा कि इसकी जरूरत नहीं थी। एक सारांश कोर्ट मार्शल को इसकी प्रभावकारिता, अंतिमता और वैधता के लिए पुष्टिकरण प्राधिकारी की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि कोर्ट मार्शल के अन्य तीन वर्गों (सुप्रा) के लिए अनिवार्य है, धारा 153 धारा 161 (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समरी कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष और सजा की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इसे तुरंत लागू किया जा सकता है। हालाँकि, धारा 162 में कार्यवाही के प्रसारण को बिना किसी देरी के सक्षम अधिकारी, उस डिविजन या ब्रिगेड के कमांडिंग

अधिकारी, या निर्धारित अधिकारी को भेजने की आवश्यकता होती है; और ऐसा अधिकारी, या सेना प्रमुख, या सेना प्रमुख द्वारा इस संबंध में अधिकार प्राप्त कोई अन्य, मामले की योग्यता के आधार पर कारणों से, न कि केवल तकनीकी आधार पर, कार्यवाही को रद्द कर सकता है या सजा को कम कर सकता है किसी अन्य सज़ा के लिए जो कोर्ट (मार्शल) ने पारित किया हो। यह धारा 162 के तहत कार्यवाही का प्रसारण है, समीक्षा प्राधिकारी के इस आग्रह का आधार है कि "दोषी नहीं" की दलील साक्ष्य के सारांश के बाद दर्ज की जानी चाहिए, जो कि प्रतिवादी द्वारा दिए गए साक्ष्य के बयान और उसके बाद की सेटिंग पर आधारित है। ऑफिसर कमांडिंग की अध्यक्षता में कोर्ट मार्शल के परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साक्ष्य के सारांश में, एक आपत्ति पर, प्रतिवादी ने केवल कोयले के हथौड़े से जबरन वसूली करने के आरोप का विरोध किया था, और उसके जवाब में कहा था कि उसने एक हथौड़े के लिए अनुरोध किया था जिसे सर्दियों के अंत में लौटाया जाना था, और वह खोलने पर बैग में दो मिले। साक्ष्य के सारांश में हाई स्पीड डीजल से जबरन वसूली के आरोप के संबंध में उसके बचाव में कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा, प्रतिवादी ने समरी कोर्ट मार्शल सुनवाई में बचाव का कोई बयान नहीं दिया, और न ही अपनी ओर से कोई बचाव गवाह पेश किया और न ही अभियोजन पक्ष के दो गवाहों में से किसी से जिरह की। इन अपरिहार्य तथ्यों का सामना करते हुए, समीक्षा प्राधिकारी ऐसे तकनीकी आधार पर कार्यवाही को रद्द नहीं कर सकता था - जिसे धारा 162 स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती है - जिसके संबंध में सेना नियम 116(4) के तहत "दोषी नहीं" की याचिका दर्ज की जानी चाहिए थी। जबरन वसूली के दोनों आरोप, क्योंकि प्रतिवादी की "दोषी" की दलील का प्रभाव उसके द्वारा पूरी तरह से समझा नहीं गया था। कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष और सजा को समीक्षा प्राधिकारी द्वारा बिना किसी बाधा के छोड़ दिया जाना चाहिए था, यह आत्मनिर्भर रूप से वैध था क्योंकि यह धारा 161 (1) के तहत था।

25. सेना अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम विशेष रूप से विचार करते हैं कि अधिनियम के अधीन एक अधिकारी के अलावा किसी भी व्यक्ति को अधिनियम की धारा 20 के तहत सेवा से बर्खास्त या हटाया जा सकता है; और ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियम 17 के साथ पठित धारा 20 के तहत बर्खास्त किया जा सकता है, हटाया जा सकता है या रैंक में कमी की जा सकती है। उच्च न्यायालय इस द्वंद्व की सराहना करने में असफल नहीं हुआ है, क्योंकि उसने विभागीय कार्यवाही करने से नहीं रोका है। अंतर यह है कि विभागीय कार्यवाही वही है जो की गई थी और इसके अतिरिक्त जो अब आक्षेपित निर्णय द्वारा शुरू करने की अनुमति दी गई है।

26. उपरोक्त स्पष्टीकरणों के साथ हम समरी कोर्ट मार्शल के आदेश को बहाल करके अपील का निपटान करते हैं, फिर भी अपीलकर्ताओं को कानून के अनुसार आगे बढ़ने से नहीं रोकते हैं।

कल्पना के.त्रिपाठी

अपील निस्तारित की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।